

भारत - माले संबंध

सामान्य : माले गणराज्य ने फ्रांस से अपनी आजादी 22 सितंबर, 1960 को प्राप्त की। यह एक उद्घोषित धर्म निरपेक्ष राज्य है। (क) माले एक भू आबद्ध देश है जो दक्षिणी उप सहारा क्षेत्र में पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। देश का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा मरुस्थल है (उत्तर - पूर्वी हिस्सा)। अनुमानित आबादी 16 से 18 मिलियन है जिसमें सुन्नी मुसलमानों की बहुलता (95 प्रतिशत के आसपास) है। अधिक आबादी वाले अधिकांश केन्द्र दक्षिण में स्थित हैं जहां दो सदाबहार नदियां बहती हैं अर्थात् नाइजर, जो देश की जीवन रेखा है तथा पश्चिम में सेनेगल। माले अफ्रीका में 8वां सबसे बड़ा देश और विश्व में 24वां सबसे बड़ा देश है। यहां की मातृभाषा बंबारा है (लगभग 80 प्रतिशत आबादी बंबारा भाषा बोलती है)। यहां की मुद्रा कम्प्युनौट फिनासियेरे अफ्रीकन फ्रैंक (सी एफ ए फ्रैंक अथवा एफ सी एफ ए) है। मोटे तौर पर एक अमरीकी डालर 560-575 एफ सी एफ ए के बराबर होता है। फ्रेंच यहां की राजभाषा है। यहां की राजधानी बमाको है।

नेतृत्व :

राष्ट्रपति : महामहिम श्री इब्राहिम बाउबाकर कीटा (4 सितंबर 2013 से)

प्रधानमंत्री : महामहिम श्री मोडिबो कीटा (8 जनवरी 2015 से)

विदेश मंत्री : महामहिम श्री अब्दुलाए डिओप (11 अप्रैल 2014 से)

देश की विदेश नीति की मुख्य प्राथमिकताएं

- i) अच्छे पड़ोसी के संबंधों, अफ्रीका के जिन देशों के साथ सीमा नहीं लगती है उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना और विश्व शांति को बढ़ावा देना।
- ii) उप क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण, अफ्रीका की एकता एवं विकास को बढ़ावा देना।
- iii) माले के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान देना।
- iv) अंतर्राष्ट्रीय मंचों में माले के बेहतर एवं कारगर प्रतिनिधित्व के लिए अधिक कारगर एवं समंवित प्रबंधन।

राजनीतिक संबंध : भारत और माले के बीच परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं तथा दोनों देशों के बीच कोई भू राजनीतिक टकराव नहीं है। भारत सरकार ने मई 2009 में बमाको में अपना दूतावास स्थापित किया। इसके शीघ्र बाद माले ने अगस्त 2009 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला था। माले में राजनीतिक एवं सुरक्षा संकट के दौरान तथा मार्च 2012 में सैन्य

तख्ता पलट के बाद भारत ने माले में संवैधानिक व्यवस्था की बहाली तथा अपनी भौगोलिक अखंडता को बनाए रखने के लिए माले के प्रयासों का भरपूर समर्थन किया। भारत ने अदिस अबाबा में आयोजित दाता सम्मेलन में माले के सुरक्षा बलों के सुदृढीकरण के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान भी दिया। अब जब सितंबर 2013 से लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो गई है, भारत सरकार ने, इस परिवर्तन का स्वागत करते हुए माले के साथ अपने विकास सहयोग की भागीदारी को और सुदृढ करने की अपनी इच्छा दोहराई है। भारत ने उपनिवेशवाद का निरंतर विरोध किया है तथा पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न स्कीमों के तहत माले को उदारतापूर्वक विकास सहायता प्रदान की है। माले भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा है। माले सरकार भारत के योगदान का आभार प्रकट करती है और भारत के साथ अपने संबंध को और सुदृढ करने की अपेक्षा रखती है।

भारत और माले के बीच द्विपक्षीय करार :

- i) विदेश कार्यालय परामर्श पर प्रोटोकॉल (2009)
- ii) राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर करार (2009)
- iii) भूविज्ञान एवं खनिज संसाधनों में सहयोग पर एम ओ यू (2012)

द्विपक्षीय यात्राएं : अनेक मंत्रियों तथा उच्च स्तरीय अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ माले गणराज्य के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के नियंत्रण पर अक्टूबर 2015 में तीसरी भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक (आई ए एफ एस 3) में भाग लिया। माले के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए निमंत्रण भी दिया। हाल के वर्षों में भारत की ओर से कोई समतुल्य / उच्च स्तरीय यात्रा नहीं हुई है। माले की प्रथम महिला ने भी 'ग्लोबल काल टू ऐक्शन समिट 2015' में भाग लेने के लिए अगस्त 2015 में भारत का दौरा किया था। उन्होंने उस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ संक्षिप्त मुलाकात भी की थी।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहायता : प्रत्यक्ष द्विपक्षीय सहायता के साथ-साथ माले ने भारत से टीम-9 (9 पश्चिमी अफ्रीकी देशों पर केंद्रित भारत-अफ्रीका आंदोलन का तकनीकी-आर्थिक उपागम), नेपाड (अफ्रीका के विकास के लिए नवीन भागीदारी) और इकोवास (पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय) बैंक के माध्यम से भारतीय सहायता प्राप्त की है।

ऋण सहायता : भारत ने माले को ग्रामीण विद्युतीकरण, ट्रैक्टरों और ट्रैक्टर असेंबली संयंत्र, रेलवे कोच और लोकोमोटिव, कोट डी' आइवरी और माले के बीच पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन, तथा विद्युत

वितरण, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए अब तक 303.62 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता प्रदान की है। बोगोनी के रास्ते सिकासो से बामाको शहर तक एक बड़ी विद्युत पारेषण परियोजना, जिसके लिए भारत ने मिलियन अमरीकी डॉलर का लाइन्स ऑफ क्रेडिट प्रदान किया था, अंतिम निविदा चरण में है और शीघ्र ही आरंभ हो जाने की उम्मीद है।

पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क परियोजना : यह परियोजना माले में चल रही है। यह परियोजना, जो सभी अफ्रीकियों को शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करने की दृष्टि से एक उपग्रह और ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए बनाई गई है, बामाको, माले में कार्यान्वयन एजेंसी टेलीकम्यूनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

डी एफ पी टी का प्रस्ताव : भारत ने माले को शुल्क मुक्त टैरिफ अधिमानता (डी एफ टी एफ) स्कीम प्रदान की थी। माले ने अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं तथा भारतीय आयातक इस छूट का लाभ पहले से ही ले रहे हैं।

खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्र का प्रस्ताव : भारत ने माले में एक खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव किया है। उम्मीद है कि शीघ्र ही भारत से विशेषज्ञों की एक टीम प्रारंभिक वार्ता आरंभ करेगी।

इबोला वायरस बीमारी (ई वी डी) 2014 का प्रकोप : माले 2014 के उत्तरार्ध में इबोला वायरस बीमारी (ई वी डी) से प्रभावित हुआ। भारत ने पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में इबोला वायरस बीमारी (ई वी डी) पर अंकुश लगाने के लिए 12.55 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक का वित्तीय योगदान दिया, हालांकि यह योगदान माले विशिष्ट नहीं था।

प्रशिक्षण सहायता : वर्तमान वित्त वर्ष में भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम के तहत माले को प्रस्तावित स्लॉटों की संख्या इस साल 30 है।

अन्य छात्रवृत्तियां :

- i) भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक I एवं II की विभिन्न पहलों के तहत।
- ii) कृषि छात्रवृत्तियों को अफ्रीकी यूनियन के माध्यम से अभिशासित किया जा रहा है।
- iii) सी वी रमन फेलोशिप स्कीम - माले को 8 स्लॉटों का प्रस्ताव किया गया है। दो स्लॉटों का उपयोग कर लिया गया है।

- iv) माले के दो सैन्य अधिकारियों ने दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है।
- v) आई सी सी आर - अफ्रीका छात्रवृत्ति स्कीम : 2016-17 के दौरान माले को 8 स्लॉटों की पेशकश की गई है।

अन्य सेक्टरल सहयोग :

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सी ई एल) ने सोलर फोटो वाल्टिक माइयूल एवं सिस्टम के विनिर्माण के लिए माले राष्ट्रीय सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा केन्द्र के लिए एक संविदा का निष्पादन किया है जिसे अब जून 2014 में अगले 5 वर्षों के लिए नवीकृत किया गया है।

द्विपक्षीय व्यापार (माले) : दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा मूल्य नगण्य है। माले विद्युत, संचार, आई टी, शिक्षा, खनन, कृषि, आटोमोबाइल एवं फार्मास्युटिकल आदि जैसे क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञता का भरपूर मात्रा में प्रयोग कर सकता है। यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है तथा विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर है। गोल्ड, पशुधन और कृषि का माले के निर्यात में अनुपात 80 प्रतिशत के आसपास है। आर्थिक मायनों में, माले को भारतीय निर्यात माले के वैश्विक आयातों के .5 प्रतिशत से कम और भारत को माले के वैश्विक निर्यात भारत के वैश्विक आयातों के .5 प्रतिशत से कम है। माले ने उदार एवं मैत्रीपूर्ण निवेश एवं व्यापार नीति अपनाई है। कृषि (कपास, खाद्य प्रसंस्करण, बूचड़खानों और चमड़ा कारखानों), ऑटोमोबाइल (दुपहिया वाहन सेगमेंट), खनन (सोना, लौह अयस्क, फॉस्फेट्स, यूरेनियम, बॉक्साइट, जस्ता, मैंगनीज, टिन और तांबा) और औषधियों (जेनरिक दवाओं) के क्षेत्र में, निवेश के प्रचुर अवसर और मौजूद हैं। इस देश में अन्य खनिजों जैसे कि ग्रेनाइट, जिप्सम, कायोलिन, चूना पत्थर, लीथियम, रॉक साल्ट, सिल्वर आदि के मौजूद होने के पक्के प्रमाण हैं जिनके दोहन की प्रतीक्षा है।

माले को भारत से निर्यात: विद्युत पारेषण के लिए उपकरण, सूती कपड़ा और मेड अप, साइकिल के पार्ट्स, मशीनरी और मशीनरी पार्ट्स, परिवहन उपकरण, दवाएं एवं औषधियां, निर्माण सामग्री एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ।

भारत को माले से निर्यात: कच्चा सूत, लकड़ी के उत्पाद और शी नट्स जैसे कुछ कृषि उत्पाद। माले भारत से विशेष रूप से खनन, विद्युत, कृषि, फार्मास्युटिकल, इंजीनियरिंग एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में और अवसंरचनात्मक एवं मानव संसाधन विकास सहायता की अपेक्षा रखता है।

माले में भारतीय निवेश : इस देश में भारतीय वस्तुओं, फार्मास्युटिकल तथा लाइट इंजीनियरिंग उत्पादों की उल्लेखनीय मौजूदगी है जहां अन्यथा चाइनीज / यूरोपीय संघ के उत्पादों की प्रचुरता है। माले में भारतीय मुख्य रूप से व्यवसाय, खनन, विद्युत, स्टील, सीमेंट, फार्मास्युटिकल तथा कृषि उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा माले में ऋण सहायता प्रदान करने से संबंधित गतिविधियों, विद्युत पारेषण, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण आदि में भी भारतीय कंपनियों की मौजूदगी है।

भारत में माले का निवेश : भारत में माले का कोई ज्ञात निवेश उद्यम नहीं है। यह विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है तथा लगभग हर क्षेत्र में विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर है।

संस्कृति

दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है जिसे सांस्कृतिक विनिमय यात्राओं के माध्यम से साझा किया जा सकता है। बालीवुड मूवी, भारतीय टेलीविजन सीरियल और भारतीय पोशाक यहां की आबादी में लोकप्रिय हैं तथा ऐसा लगता है कि माले का आम नागरिक भारत को बहुत सम्मान की नजरों से देखता है। आई ए एफ एस 3 के दौरान एक म्यूजिकल परफार्मेंस के लिए दो सदस्यीय सांस्कृतिक शिष्टमंडल भारत के दौरे पर आया था तथा उसने बहुत प्रशंसा हासिल की। भारत और माले के बीच संभवतः एक मात्र उल्लेखनीय परंतु दूरस्थ लिंक टिंबकट्ट का नामचीन शहर है। दूर स्थित भारतीयों के लिए माले का टिंबकट्ट विश्व के कल्पित अंतिम छोर पर स्थित लिजेंडरी स्थल है। तथापि सच्चाई यह है कि यह शहर सहारा मरुस्थल के दक्षिण छोर पर स्थित है तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सदियों तक वाणिज्य, शिक्षा और संस्कृति का केन्द्र रहा है। जून 2015 में भारतीय दूतावास में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आई डी वाई) में संस्कृति, पर्यटन एवं हस्तशिल्प मंत्री मुख्य अतिथि थे। माले ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने से संबंधित भारत के यू एन संकल्प का सह प्रायोजक था और इसके पक्ष में मतदान किया था।

माले में भारतीय समुदाय: माले में भारतीयों की अनुमानित संख्या 200 से 250 के बीच है। मुख्य रूप से वे फुटकर व्यवसाय, खनन, विद्युत, स्टील, सीमेंट, भेषज पदार्थ और कृषि उद्योग के क्षेत्रों में हैं। इनमें एल ओ सी परियोजना के कर्मचारियों तथा विदेशी कंपनियों के साथ अन्य पेशेवरों का अनुपात काफी है। यू एन शांति रक्षा मिशन मिनुसमा (माले में यू एन बहुआयामी एकीकृत स्थिरता मिशन) के लिए लगभग 35 भारतीय सिविलियन ठेकेदार / कर्मचारी हैं। माले में विरल भारतीय समुदाय का कोई ज्ञात संगठन / संघ नहीं है।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय दूतावास, बामाको की वेबसाइट:

<http://www.amb-inde-bamako.org/>

भारतीय दूतावास, बामाको का फेसबुक पृष्ठ:

<https://www.facebook.com/indembassybamako>

जनवरी, 2016